

## विषय-वस्तु

पैरा सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
क	उद्देश्य	4
ख	वर्गीकरण	4
ग	पिछले समेकित दिशानिर्देश	4
घ	प्रयोज्यता का दायरा	4
1.	प्रस्तावना	5
2.	सहायक कंपनियां	5
3.	सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों में अधिकतम निवेशसीमा	5
4.	सहायक कंपनियों के साथ संबंध	8
5	संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	9
6	उद्यम पूंजी निधियों (वीसीएफ) में बैंक का निवेश	10
7	इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों (आईडीएफ) के प्रायोजक के रूप में बैंक	10
8.	उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद कारोबार और आदत सेवाएं	11
9.	प्राथमिक व्यापारियों का कारोबार	14
10	हामीदारी गतिविधियां	17
11	सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री	18
12	पारस्परिक निधि (म्युच्युअल फंड) व्यवसाय	18
13	मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियां	19
14.	मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों के निवेशकों को "चेक लिखने" की सुविधा	20
15.	बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश	21
16.	बैंकों द्वारा पेंशन निधि प्रबंधन (पीएफएम)	23
17.	सिफारिशी सेवाएं	24
18.	सेबी अनुमोदित शेयर बाजार में कारोबार/ सदस्यता	24
19	पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ	25
20	'सेफ्टी नेट' योजनाएं	27
21.	शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण	28
<b>अनुबंध-1</b> वित्तीय सेवा कंपनी		30
<b>अनुबंध-2</b> भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी, संयुक्त उद्यम, 'नियंत्रण और महत्वपूर्ण प्रभाव' की परिभाषा		32

अनुबंध -3 बीमा ब्रोकिंग तथा एजेंसी व्यवसाय करने वाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश	34
अनुबंध - 4 पेंशन निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश	37
परिशिष्ट - मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	40

## मास्टर परिपत्र - परा-बैंकिंग कार्यकलाप

### **क. उद्देश्य:**

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के अनुसार क्रेडिट, डेबिट तथा प्रीपेड कार्ड जारी करने को छोड़कर जिसके लिए एक अलग मास्टर परिपत्र जारी किया गया है, कुछ वित्तीय सेवाएं अथवा परा-बैंकिंग (बैंकिंग से इतर) कार्यकलाप करने के लिए नियमों/विनियमों/ अनुदेशों का एक ढांचा प्रदान करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय सेवाएं अथवा परा-बैंकिंग कार्यकलाप सुदृढ़ और विवेकपूर्ण आधार पर किये जाते हैं, बैंकों को पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए तथा निम्नलिखित दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करना चाहिए।

**ख. वर्गीकरण:** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया सांविधिक दिशानिर्देश।

### **ग . पिछले समेकित दिशानिर्देश:**

इस मास्टर परिपत्र में परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को समेकित किया गया है।

### **घ. प्रयोज्यता का दायरा**

ये दिशानिर्देश उन सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होते हैं जो विभागीय कार्यकलापों के रूप में अथवा अपनी सहायक कंपनियों अथवा उनके द्वारा नियंत्रित संबद्ध कंपनियों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं अथवा परा-बैंकिंग कार्यकलाप करते हैं।

## 1. प्रस्तावना

बैंक कुछ पात्र वित्तीय सेवाओं या पैरा-बैंकिंग कार्यकलापों को विभागीय रूप में अथवा सहायक संस्थाएं स्थापित करके प्रारंभ कर सकते हैं। बैंक इस प्रकार का कारोबार, जिसके लिए किसी बैंकिंग कंपनी को अन्यथा अनुमति है, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से सहायक संस्थाएं स्थापित करके प्रारंभ कर सकते हैं। इस मास्टर परिपत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत विभिन्न वित्तीय सेवाओं अथवा परा-बैंकिंग (बैंकिंग से इतर) कार्यकलाप करने हेतु जारी अनुदेशों को संकलित किया गया है।

## 2. सहायक कंपनियां

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(1) के उपबंधों के अंतर्गत बैंक निम्नलिखित प्रयोजनों से सहायक कंपनियाँ स्थापित कर सकते हैं - (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6, उपधारा (1) खंड (क) से (ण) के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमेय बैंकिंग कारोबार करने के लिए, (ii) केवल भारत के बाहर बैंकिंग कारोबार करने के लिए और (iii) ऐसे अन्य कारोबारी प्रयोजनों के लिए जिसे केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय रिज़र्व बैंक भारत में बैंकिंग के प्रसार के लिए अथवा जनहित में उपयोगी या आवश्यक समझता है। सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक है।

## 3. सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों में अधिकतम निवेश सीमा

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के उपबंधों के अंतर्गत कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी भी कंपनी में गिरवीदार या बंधकग्राही के रूप में या संपूर्ण स्वामी के रूप में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत या अपनी प्रदत्त शेयर पूंजी व आरक्षित निधियों का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक राशि के शेयर धारित नहीं कर सकती है। तथापि, सहायक कंपनियों के विपरीत उन कंपनियों के कार्यकलापों पर कोई सांविधिक प्रतिबंध नहीं है जिनमें बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) के अंतर्गत यथानिर्धारित उच्चतम सीमा के भीतर ईक्विटी धारित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ये कंपनियां वित्तीय सेवाएं कंपनियां तथा ऐसी कंपनियां भी हो सकती हैं जो वित्तीय सेवाओं से नहीं जुड़ी हैं।

### 3.1 सहायक कंपनियों तथा वित्तीय सेवा कंपनियों में निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमावली

- (क) किसी सहायक कंपनी, अथवा वित्तीय संस्था, शेयर तथा अन्य बाजारों, निक्षेपागारों आदि सहित किसी वित्तीय सेवा कंपनी जो सहायक कंपनी न हो, में किसी बैंक का निवेश बैंक की चुकता शेयर पूंजी व आरक्षित निधियों के 10 प्रतिशत तथा सभी सहायक कंपनियों एवं अन्य संस्थाओं जो गैर-वित्तीय सेवा गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं में इक्विटी निवेश के साथ-साथ वित्तीय सेवा गतिविधियों में संलग्न है, में कुल निवेश बैंक की चुकता शेयर पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- (ख) तथापि, बैंक शेयर बाजारों, डिपॉजिटरीज इत्यादि सहित किसी भी वित्तीय सेवा उद्यम में भारतीय रिज़र्व बैंक के स्पष्ट पूर्वानुमोदन के बिना इक्विटी शेयरों में सहभागी नहीं बन सकता, भले ही, इस प्रकार के निवेश बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर हों।
- (ग) तथापि, यदि वित्तीय सेवा कंपनियों में निवेश 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत धारित हैं तथा उन्हें 90 दिन से अधिक समय के लिए धारित नहीं किया गया है तो न तो 20 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लागू होती है और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है ।

### 3.2 गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों में बैंकों के निवेश पर विवेकपूर्ण विनियमावली

चूंकि गैर-वित्तीय सेवा कंपनियों में निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है इसलिए बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के उपबंधों के अंतर्गत इन कंपनियों में संभावित रूप से काफी इक्विटी धारण कर सकते हैं । अतः यह संभव है कि अन्य कंपनियों में अपनी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष धारिताओं के माध्यम से बैंक ऐसी कंपनियों पर नियंत्रण रख रहे हों और काफी हद तक उन्हें प्रभावित कर रहे हों और इस प्रकार ऐसे कार्यकलापों में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हों जिनके लिए बैंकों को अनुमति नहीं दी गयी है । यह स्थिति अधिनियम के उपबंधों के आशय के विपरीत होगी और विवेकपूर्ण दृष्टि से उचित नहीं मानी जाएगी। अतः गैर वित्तीय सेवा कम्पनियों में निवेश को सीमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं :

- (क) गैर-वित्तीय सेवा कार्यकलापों के साथ जुड़ी कंपनियों में किसी बैंक का इक्विटी निवेश निवेशिती कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत या बैंक की चुकता शेयर पूंजी एवं आरक्षित निधियों के 10 प्रतिशत, इनमें से जो कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए। 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत धारित इक्विटी निवेशों को भी हिसाब में लिया जाएगा। उपर्युक्त सीमाओं के भीतर किए गए निवेशों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं होगा भले ही वे निवेश 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी में हो या न हों ।
- (ख) किसी गैर-वित्तीय सेवा कंपनी में (क) किसी बैंक; (ख) ऐसी कंपनियां जो बैंक की सहायक कंपनियां, सहयोगी कंपनियां या संयुक्त उपक्रम या बैंक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कंपनियाँ हों; तथा (ग) बैंक द्वारा नियंत्रित आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) द्वारा प्रबंधित म्युचुअल फंडों द्वारा किया गया निवेश कुल मिलाकर निवेशिती कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ग) ऐसी निवेशिती कंपनी में उसकी चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक लेकिन 30 प्रतिशत से कम निवेश करने के लिए किसी बैंक के अनुरोध पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तभी विचार किया जाएगा यदि उक्त निवेशिती कंपनी ऐसे गैर-वित्तीय कार्य कलापों से जुड़ी हो जिनके लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6(1) के अनुसार बैंकों को अनुमति दी गई है ।
- (घ) किसी बैंक का सहायक कंपनियों तथा वित्तीय सेवा कार्यकलापों से जुड़ी अन्य कंपनियों के साथ-साथ गैर-वित्तीय सेवा कार्यकलापों से जुड़ी कंपनियों में कुल इक्विटी निवेश उक्त बैंक की चुकता शेयर पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों जिन्हें 90 दिन से अधिक के लिए नहीं धारित किया गया है, पर 20 प्रतिशत की उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी ।
- (ङ) किसी गैर-वित्तीय सेवा निवेशिती कंपनी में उसकी चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक इक्विटी धारिता की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के अनुसार 30 प्रतिशत की सांविधिक सीमा के अधीन) के बिना की जा सकती है यदि अतिरिक्त धारिता को

पुनर्रचना/कार्पोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था (सीडीआर) के माध्यम से अथवा किसी कंपनी में बैंक द्वारा अपने ऋण/किए गए निवेशों पर अपने हित के बचाव के लिए अर्जित किया गया हो। ऐसे मामलों में निवेशिती कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी निवेश को उपर्युक्त 20 प्रतिशत सीमा से छूट प्राप्त होगी। तथापि, बैंकों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ऐसे शेयरों के निपटान के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

3.3 उपर्युक्त दिशानिर्देशों के प्रयोजन से वित्तीय सेवा कंपनी का अर्थ **अनुबंध-1** में दिये गये ब्यौरे के अनुसार होगा। साथ ही, सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यम जैसे शब्दों का अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211(3ग) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित लेखा पद्धति मानकों द्वारा निर्धारित किया गया है (**अनुबंध-2** के रूप में उद्धरण संलग्न)।

#### 4. सहायक कंपनियों के साथ संबंध

यह जरूरी है कि प्रयोजक बैंक व्यवसाय - मानदंडों के बारे में सहायक कंपनी/पारस्परिक निधि से उचित दूरी बनाएं रखें। ये मानदंड इस प्रकार हैं - निधियाँ उधार लेने/उधार देने में अनुचित लाभ उठाना, बाजार दर से भिन्न दरों पर प्रतिभूतियां अंतरित करना/बेचना/खरीदना, प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए विशिष्ट प्रतिफल देना, सहायक कंपनियों को समर्थन/वित्त पोषण में विशेष रुचि दिखाना, सहायक संस्थाओं के माध्यम से बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना वह भी ऐसे समय जब बैंक ऐसा करने में समर्थ नहीं है या ऐसा करने की अनुमति उसे नहीं है, इत्यादि। तथापि, प्रायोजक बैंक द्वारा किये जाने वाले पर्यवेक्षण से सहायक संस्था/पारस्परिक निधि के दैनिक कामकाज में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित नहीं होना चाहिए। बैंकों को उपयुक्त नीति बनानी चाहिए जैसे:

(क) मूल/प्रायोजक बैंक का निदेशक बोर्ड सहायक कंपनियों/पारस्परिक निधि की कार्यपद्धति की सामयिक अंतराल पर (छ: महीने में एक बार) समीक्षा करेगा। ऐसी समीक्षा में इन संस्थाओं की कार्यपद्धति के संबंधित प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाएगा और जरूरी समझे जाने पर सुधार के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत/सुझाव देगा।

(ख) मूल बैंक सहायक कंपनियों/पारस्परिक निधियों की बहियों और लेखों का उचित सामयिक अंतराल पर निरीक्षण/लेखा-परीक्षा करवाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ध्यान में लाई गई कमियों को बिना विलंब के ठीक किया जाता है। यदि किसी बैंक का अपना स्टाफ निरीक्षण/लेखा-परीक्षा करने के लिए पर्याप्त साधन संपन्न नहीं है तो यह

कार्य सनदी लेखाकारों की फर्म जैसी बाहरी एजेंसियों को सौंपा जा सकता है। यदि निरीक्षण/लेखा-परीक्षा करवाने में कोई तकनीकी कठिनाई है (जैसे सहायक कंपनी अथवा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के अंतर्नियमों तथा बहिर्नियमों में अधिकार प्रदान करने वाला खंड का न होना) तो ऐसे अंतर्नियमों व बहिर्नियमों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

- (ग) वित्तीय सेवाएं प्रस्तावित करनेवाली कंपनियों में यदि संविभागीय निवेश के रूप में बैंकों की इक्विटी सहभागिता है तो वे ऐसी कंपनियों के कार्य की कम-से-कम वार्षिक आधार पर समीक्षा कर सकते हैं।

## 5. संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ संबंध

बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के परिचालन क्षेत्र में विनियामक अंतरालों के कारण विनियामक अंतरापणन की संभावना बढ़ जाती है और असमान अवसर तथा संभाव्य संपूर्ण प्रणालीगत जोखिम बढ़ जाता है। इस प्रकार बैंकों को सूचित किया जाता है कि संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ बैंकों के संबंध के बारे में नीचे दिए गए विनियामक ढाँचे का पालन करें:

- (क) भारत में मौजूदगी वाले विदेशी बैंक के मूल/ समूह द्वारा प्रवर्तित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो विदेशी बैंक की मूल कंपनी/ समूह की सहायक कंपनी है अथवा जहां मूल कंपनी/ समूह का प्रबंध नियंत्रण है, उसे भारत में उस विदेशी बैंक के परिचालनों का एक भाग माना जाएगा तथा समेकित पर्यवेक्षण के अधीन लाया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, संबंधित विदेशी बैंक उपर्युक्त दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित समेकित विवेकपूर्ण विवरणियां (सीपीआर) बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को प्रस्तुत करेंगे तथा उन दिशानिर्देशों में निर्धारित भारत में उस बैंक के समेकित परिचालनों पर लागू होने वाले विवेकपूर्ण विनियमों/ मानदंडों का अनुपालन भी करेंगे। भारत में कार्यरत इन विदेशी बैंकों को लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण एएस के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। वे सहायक कंपनियों के समेकन पर लागू एएस 21 के सिद्धांतों को अपनाकर समेकित विवेकपूर्ण विनियमों के प्रयोजन से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंक के भारतीय परिचालनों के साथ पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर सकते हैं। जहाँ किसी विदेशी बैंक के पास किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निर्गमित तथा प्रदत्त इक्विटी की 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत (दोनों शामिल) के बीच की धारिता होगी, वहां यदि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को



समेकित विवेकपूर्ण विनियमों के क्षेत्र के बाहर रखना है तो उक्त विदेशी बैंक को यह सिद्ध करना होगा कि उसके पास प्रबंध नियंत्रण नहीं है।

(ख) भारत में कार्यरत बैंक, जिनमें भारत में कार्यरत विदेशी बैंक शामिल हैं, जमाराशि लेने वाली किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 10% से अधिक अंश नहीं रखेगा। तथापि, यह प्रतिबंध आवास वित्त कंपनियों में निवेश पर लागू नहीं होगा।

## 6. उद्यम पूंजी निधियों में बैंक का निवेश

उद्यम पूंजी गतिविधियों का महत्व और उद्यम पूंजी निधियों के वित्तपोषण में बैंकों की संबद्धता की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में ऐसे निवेशों में निहित अपेक्षाकृत उच्चतर जोखिमों का निवारण करना भी महत्वपूर्ण है।

तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुपालन के साथ-साथ उपर पैरा 3.1 में दी गयी विवेकपूर्ण अपेक्षाएं तथा 23 अगस्त 2006 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 27/21.01.002/2006-07 के माध्यम से उद्यम पूंजी निधियों के वित्तपोषण से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें यह निहित है कि उद्यम पूंजी निधियों में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए अर्थात् 10 प्रतिशत इक्विटी / यूनिट से अधिक निवेश करने के लिए बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।

## 7. इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों के प्रायोजक के रूप में बैंक

इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को दी जाने वाली दीर्घकालिक निधियों के प्रवाह में तेजी लाने एवं उसमें वृद्धि करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को आईडीएफ के प्रायोजक के रूप कार्य करने की अनुमति दी गयी है। आईडीएफ की स्थापना म्यूचुअल फंड (एमएफ) अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में की जा सकती है। जहां आईडीएफ-एमएफ का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाएगा, वहीं आईडीएफ एनबीएफसी का विनियमन भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) करेगा। बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, आईडीएफ-एमएफ तथा आईडीएफ-एनबीएफसी के प्रायोजक के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी :

(i) *आईडीएफ-एमएफ का प्रायोजक*

बैंक आईडीएफ-एमएफ के प्रायोजक के रूप में कार्य कर सकते हैं बशर्ते वे इस संबंध में सेबी के विनियमों का पालन करें ।

(ii) *आईडीएफ-एनबीएफसी का प्रायोजक*

आईडीएफ-एनबीएफसी के प्रायोजक के रूप में कार्यरत बैंक की आईडीएफ-एनबीएफसी में न्यूनतम 30 प्रतिशत और अधिकतम 49 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी होगी । चूंकि बैंककारी विनियमन, 1949 की धारा 19(2) के अनुसार कोई बैंक तब तक किसी कंपनी की चुकता शेयर पूंजी के 30 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित नहीं कर सकता जब तक वह कोई सहायक कंपनी न हो इसलिए गुण-दोष के आधार पर रिज़र्व बैंक आईडीएफ-एनबीएफसी की इक्विटी में 30 प्रतिशत से अधिक तथा 49 प्रतिशत तक निवेश करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 19 (2) के उपबंधों से छूट देने के लिए (अर्थात् उक्त अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत) सरकार से सिफारिश करेगा ।

(iii) *म्यूचुअल फंड (एमएफ) तथा एनबीएफसी दोनों संरचनाओं के अंतर्गत आईडीएफ के प्रायोजक के रूप में कार्य करने के लिए बैंकों पर लागू होने वाली सामान्य शर्तें*

- (क) एकल आईडीएफ-एमएफ अथवा आईडीएफ-एनबीएफसी की इक्विटी में बैंक का निवेश उपर्युक्त पैराग्राफ 3.1 (क) तथा (ख) में दी गई विवेकपूर्ण सीमाओं के अधीन होगा।
- (ख) आईडीएफ (आईडीएफ-एमएफ तथा आईडीएफ एनबीएफसी दोनों ही में) बैंक का एक्सपोजर, प्रायोजकों के रूप में चुकता पूंजी में किया गया अंशदान उसके पूंजी बाजार का भाग होगा और उसे इस संबंध में निर्दिष्ट विनियामक सीमाओं के भीतर होना चाहिए।
- (ग) बैंकों के पास अपने संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोजर के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्पष्ट नीतियां तथा सीमाएं होनी चाहिए जिसमें आईडीएफ-(एमएफ तथा एनबीएफसी) के प्रायोजक के रूप में उनका एक्सपोजर भी शामिल होना चाहिए ।
- (घ) आईडीएफ-(एमएफ तथा एनबीएफसी) को निवेश आंमत्रित करते समय अपनी परिचय-पुस्तिका/ऑफर दस्तावेज में यह सूचना प्रकट करनी चाहिए कि प्रायोजक बैंक की देयता चुकता पूंजी में उसके अंशदान की सीमा तक ही सीमित है।

## 8. उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद कारोबार और आढ़त सेवाएं

8.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से बैंक उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद व्यवसाय और आढ़त सेवाएं प्रारंभ करने के लिए सहायक कंपनियाँ स्थापित कर सकते हैं। बैंकिंग कंपनियों द्वारा इस प्रकार का कारोबार किया जाना निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अधीन होगा:

- (क) इस प्रकार स्थापित की गई सहायक कंपनियाँ / संयुक्त उद्यम मुख्यतः उपर्युक्त कार्यकलापों में तथा उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद व्यवसाय और आढ़त सेवाओं से संबद्ध अन्य प्रासंगिक कार्यकलापों में कार्यरत होनी चाहिए। इन सहायक कंपनियों को अन्य कंपनियों या ऐसी कंपनियों के उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद व्यवसाय और आढ़त सेवाओं से संबद्ध प्रतिष्ठानों का वित्तपोषण नहीं करना चाहिए। इन सहायक कंपनियों को प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर भी उन कंपनियों के शेयर या डिबेंचर नहीं लेने चाहिए।
- (ख) यद्यपि बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19(2) में निर्धारित सीमा के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से अन्य उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद व्यवसाय और आढ़त कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, तथापि वे ऐसी कंपनियों के प्रमोटरों के रूप में कार्य नहीं करेंगे।
- (ग) आढ़त कंपनियों के शेयरों में जिसमें आढ़त कारोबार में लगी उनकी सहायक कंपनियां भी शामिल हैं, में बैंक का निवेश, समग्र रूप में, बैंक की चुकता पूंजी और आरक्षित निधियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (घ) किसी सहायक कंपनी की स्थापना के संबंध में या बाद में पूंजी निर्गम के लिए किये गये आवेदन पर भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन लिया जाना आवश्यक है।

8.2 बैंक उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद और आढ़त सेवाएं विभागीय रूप में भी प्रारंभ कर सकते हैं। ये सेवाएं विभागीय रूप से प्रारंभ करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है। तथापि, बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे कार्यकलापों की प्रकृति के साथ-साथ उन शाखाओं के नामों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को दें जहाँ इन कार्यकलापों की शुरुआत की गई है। इन कार्यकलापों को विभागीय रूप से प्रारंभ करते समय बैंकों को निम्नलिखित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए:

- (क) चूँकि उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद और आढ़त सेवाएं जैसे कार्यकलापों के लिए विशेष कुशलता प्राप्त कर्मचारी और पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं आवश्यक होती हैं।

इसलिए ऐसे कार्यकलाप बैंकों की कुछ चुनी हुई शाखाओं द्वारा ही प्रारंभ किये जाने चाहिए।

- (ख) इन कार्यकलापों को ऋण और अग्रिमों के समकक्ष माना जाएगा और तदनुसार, जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात का परिकलन करते समय उन्हें 100 प्रतिशत जोखिम-भारांकन दिया जायेगा। इसके साथ ही आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन संबंधी वर्तमान दिशा-निर्देश उन पर लागू होंगे।
- (ग) उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद वित्त और आढ़त सेवाओं के रूप में दी जाने वाली सुविधाएं अधिकतम ऋण सीमाओं के अंतर्गत शामिल होंगी। बैंक कुल ऋण के साथ उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद और आढ़त सेवाओं के ऋण पोर्टफोलियो का संतुलन बनाएं रखें। इनमें से किसी भी कार्यकलाप में उनका निवेश कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (घ) बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने-अपने बोर्ड के अनुमोदन से पट्टेदारी व्यवसाय के संबंध में उपयुक्त नीति बनाएं और आस्ति - देयता की संभावित विसंगति को टालने के लिए सुरक्षा मानदंड बनाएं। जहां बैंक ऐसी नीति के अनुरूप पट्टेदारी वित्त की अवधि निश्चित करने के लिए स्वतंत्र हैं वहां उन्हें इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित लेखा मानक 19 (एस 19) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- (ङ) पट्टे पर दी गयी आस्ति के अनर्जक होने से पूर्व उपचय आधार पर आय खाते में जमा वित्त आय (काउन्सिल ऑफ दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी 'पट्टे पर एस 19' के अंतर्गत यथापरिभाषित) के वित्त प्रभार घटक की प्रतिकूल प्रविष्टि की जाए अथवा चालू लेखा अवधि में उसके लिए प्रावधान किया जाए बशर्ते उसका भुगतान न किया गया हो।
- (च) आस्ति वर्गीकरण, आय निर्धारण और ऋण /अग्रिमों तथा अन्य ऋण सुविधाओं के लिए प्रावधान से संबंधित किए गए परिवर्तन विभागीय रूप से पट्टेदारी के कार्यकलाप प्रारंभ करने वाले बैंकों की पट्टे पर दी गई आस्तियों पर भी लागू होंगे।
- (छ) उपकरण पट्टे पर देने वाली कंपनियों तथा यह कार्य करने वाली अन्य गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के साथ बैंकों को पट्टेदारी करार नहीं करना चाहिए।
- (ज) पट्टेदारी का व्यवसाय करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को किसी आस्ति को उप-पट्टेदारी पर देने से प्राप्त होने वाले किराये की राशि ऐसी कंपनी के लिए बैंक वित्त की गणना में शामिल नहीं की जायेगी।
- (झ) जो बैंक विभागीय रूप से आढ़त सेवाएं प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें खरीदे गये इनवायसेस को ध्यान में लेते हुए ग्राहक की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताएं सावधानी से तय करनी चाहिए। आढ़त सेवाएं केवल उन्हीं इनवायसेस के संबंध में दी जानी चाहिए जो असली व्यापार संबंधी लेन देन के द्योतक हों। बैंक यह सुनिश्चित

करने के लिए विशेष सावधानी बरतें कि आढ़त सेवाएं प्रदान करने से ग्राहकों को आवश्यकता से अधिक वित्त तो नहीं मिल रहा है।

- (ज) बैंकों को उनके द्वारा की गई उपकरण पट्टेदारी, किराया खरीद और आढ़त सेवाओं आदि के संदर्भ में समीक्षा रिपोर्ट वार्षिक आधार पर अपने निदेशक मंडल/प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।

8.3 बैंक उधारों के संदर्भ में बैंकों को आढ़तियों द्वारा प्राप्यराशि की आढ़त के संबंध में निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए :

- (क) बैंकों और आढ़तियों को साझा उधारकर्ताओं के बारे में आपस में जानकारी का आदान-प्रदान करना चाहिए। बैंकों के लिए इस प्रकार की जानकारी किस प्रारूप में उपलब्ध करायी जाए इसका निर्णय भारतीय बैंक संघ द्वारा किया जाएगा।
- (ख) बैंकों को आढ़त किये गये बुक डेट के असाइनमेंट को सुविधाजनक बनाने के लिए आढ़तिया को दावात्याग पत्र जारी करना चाहिए तथा आढ़तियों को इसके बदले में चुकौती की राशि और अंतिम समायोजन उधारकर्ताओं के बैंक के माध्यम से रूट करना चाहिए। कंसोर्टियम के मामले में, वसूली की राशि संघ के प्रधान के माध्यम से, रूट करना चाहिए तथा एकाधिक बैंकिंग के मामले में यह निर्णय प्रत्येक बैंक अपने हितों की रक्षा करते हुए ले सकते हैं।
- (ग) उधारकर्ताओं को बैंक क्रेडिट के आकलन संबंधी अपने अनुमान में आढ़त किए जाने वाले प्रस्तावित बुक डेट की मात्रा तथा जिनके बदले में बैंक वित्त प्राप्त करना है, उनकी अलग-अलग घोषणा करनी चाहिए। उधारकर्ता को ऋण मंजूर करते समय आढ़त के अंतर्गत ली गयी सहायता को भी बैंकों को विचार में लेना चाहिए। दोहरे वित्तपोषण से बचने के लिए उधारकर्ता के बैंक को आढ़त प्राप्तियों के संबंध में उधारकर्ता से आवधिक प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए।
- (घ) दोहरे वित्तपोषण से बचने के लिए आढ़तियों को उधारकर्ता को मंजूर सीमा तथा फैक्टर किए गए डेट के बारे में संबंधित बैंक/कों को सूचना देनी चाहिए। बैंक द्वारा उधारकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र के साथ इसकी जाँच की जा सकती है।

## 9. प्राथमिक व्यापारियों का कारोबार

प्राथमिक व्यापारी कारोबार में बैंकों को शामिल करने के उद्देश्य से इस कारोबार के अनुमत ढांचे का विस्तार किया गया है। निम्नलिखित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करनेवाले बैंक प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

### 9.1 पात्रता मानदंड

निम्नलिखित श्रेणियों के बैंक पीडी लाइसेंस हेतु आवेदन कर सकते हैं:

- (i) ऐसे बैंक जिनकी वर्तमान में अंशतः अथवा पूर्णतः स्वामित्व वाली कोई सहायक कंपनी नहीं है और जो निम्नलिखित मानदंडों की पूर्ति करते हैं;
- (क) 1000 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियां हैं
  - (ख) 9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर है
  - (ग) निवल अनर्जक आस्तियां 3 प्रतिशत से कम और पिछले तीन वर्ष में लाभ कमाने का रिकार्ड है
- (ii) ऐसे भारतीय बैंक जो अंशतः अथवा पूर्ण स्वामित्ववाली किसी सहायक संस्था के जरिए प्राथमिक व्यापार प्रारंभ करने जा रहे हैं और जो अपनी अंशतः अथवा पूर्णतः स्वामित्ववाली सहायक संस्था से विलयन करके/उनसे प्राथमिक व्यापार लेकर विभागीय स्तर पर प्राथमिक व्यापार करने का प्रस्ताव करते हैं उन्हें उपर्युक्त 9.1.(i)(क) से (ग) में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करना होगा।
- (iii) भारत में कार्य करनेवाले विदेशी बैंक जो समूह कंपनियों द्वारा लिये जानेवाले प्राथमिक व्यापार का विलयन करके विभागीय स्तर पर प्राथमिक व्यापार करने का प्रस्ताव करते हैं उन्हें भी उपर्युक्त 9.1.(i) (क) से (ग) में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करना होगा।

## 9.2 प्राथमिक व्यापारी हेतु आवेदन

प्राथमिक व्यापारी हेतु आवेदन करने के लिए पात्र बैंकों को सिद्धांत रूप में अनुमोदन हेतु बैंकिंग विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करना होगा। बैंकिंग विनियमन विभाग से सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बैंकों को विभागीय तौर पर पीडी व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किए जाने हेतु आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, को आवेदन करना होगा। मंजूर किया गया प्राधिकरण आईडीएमडी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

## 9.3 विवेकपूर्ण मानदंड

- (i) पूंजी पर्याप्तता तथा जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश बैंकों के लिए प्रयोज्य विद्यमान दिशानिर्देश की तरह होंगे। बैंक की पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं तथा जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की व्याप्ति के आकलन के लिए प्राथमिक व्यापार कार्यकलापों को भी ध्यान में लेना चाहिए।

- (ii) प्राथमिक व्यापारी कारोबार के अंतर्गत सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों की सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) के लिए गणना की जाएगी, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इनको सांविधिक चल निधि अनुपात प्रतिभूतियों के रूप में अधिसूचित किया गया हो।
- (iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' पोर्टफोलियो के संबंध में बैंकों पर लागू निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण मूल्यांकन तथा परिचालन दिशानिर्देश प्राथमिक व्यापारी कारोबार के लिए निश्चित की गयी सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों तथा खजाना बिलों के पोर्टफोलियो पर भी लागू होंगे।

#### 9.4 विनियमन और पर्यवेक्षण

- (i) प्राथमिक व्यापारियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश बैंक-प्राथमिक व्यापारियों पर यथाप्रयोज्य लागू होंगे।
- (ii) चूंकि बैंकों को मांग मुद्रा बाज़ार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) सुलभ है, इसलिए बैंक-प्राथमिक व्यापारियों को अलग से यह सुविधा तथा स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों को प्रदत्त चलनिधि सहायता नहीं मिलेगी।
- (iii) भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक -प्राथमिक व्यापारी कारोबार का ऑन साइट निरीक्षण करेगा।
- (iv) बैंक-प्राथमिक व्यापारियों को निर्धारित विवरणी, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचित किये अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।
- (v) बैंक-प्राथमिक व्यापारी को चाहिए कि वह अपने विरुद्ध किसी भी बड़ी शिकायत को अथवा स्टाक एक्सचेंज, सेबी, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर आदि जैसे प्राधिकारियों द्वारा अपने विरुद्ध शुरू की गयी/की गयी कार्रवाई को भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाए।
- (vi) यदि भारतीय रिज़र्व बैंक की दृष्टि में संबंधित बैंक ने किसी भी निर्धारित पात्रता और कार्य निष्पादन मानदंड की पूर्ति न की हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंक-प्राथमिक व्यापारी का प्राधिकरण निरस्त करने का अधिकार होगा।

#### 9.5 प्राथमिक व्यापारियों के लिए जारी दिशानिर्देशों की बैंक-प्राथमिक व्यापारियों पर प्रयोज्यता

- (i) बैंक-प्राथमिक व्यापारी हामीदारी और स्टैंड अलोन प्राथमिक व्यापारियों पर लागू होने वाली अन्य बाध्यताओं, जिनका निर्धारण समय समय पर किया जाएगा, के अधीन होंगे।
- (ii) बैंक-प्राथमिक व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई) तथा नियत आय मुद्रा बाज़ार और डेरिवेटिव्स संघ (एफआइएमएमडीए) में शामिल हों तथा उनके द्वारा निर्धारित आचरण संहिता तथा प्रतिभूति बाज़ार के हित में उनके द्वारा प्रारंभ की गई ऐसी अन्य कार्रवाइयों का पालन करें।

(iii) निवल मांग (नेट कॉल)/भारतीय रिज़र्व बैंक उधार तथा निवल स्वाधिकृत निधियों के आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों में दैनंदिन आधार पर न्यूनतम निवेश सुनिश्चित करने की अपेक्षा बैंक-प्राथमिक व्यापारियों पर लागू नहीं होगी।

- (iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि 3 मई 2006 के परिपत्र आइडीएमडी. सं/3426/11.01.01 (डी)/2005-06 द्वारा अनुमत "जब जारी व्यापार" के प्रयोजन के लिए बैंक-प्राथमिक व्यापारियों को प्राथमिक व्यापारी समझा जाएगा।
- (v) मांग/सूचना पर देय/मीयादी मुद्रा बाज़ार, अंतर-कंपनी जमाराशियों, एफसीएनआर (बी) ऋण/बाहरी वाणिज्यिक उधार तथा निधियों के अन्य स्रोतों से उधार लेने के मामले में बैंक-प्राथमिक व्यापारी, बैंकों पर लागू विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे।
- (vi) बैंक की निवेश नीति में प्राथमिक व्यापारी कार्यकलापों को भी शामिल करने के लिए समुचित संशोधन किए जाएं। निवेश नीति के समग्र ढांचे के अंतर्गत बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन, हामीदारी तथा बाज़ार निर्माण तक सीमित रहेगा। कॉर्पोरेट/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/वित्तीय संस्था के बॉण्ड, वाणिज्यिक पत्रों, जमा प्रमाणपत्रों/ऋण म्युच्युअल फंडों तथा अन्य नियत आय प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय का भाग नहीं समझा जाएगा।

#### 9.6 लेखा बहियों का रख-रखाव

- (i) बैंक द्वारा विभागीय तौर पर किए गए प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय से संबंधित लेनदेन बैंक के विद्यमान अनुषंगी सामान्य खाता बही (एसजीएल) खाते के माध्यम से निष्पादित होंगे। तथापि, ऐसे बैंकों को प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय (सामान्य बैंकिंग व्यवसाय से भिन्न) से संबंधित लेनदेन के लिए लेखा-परीक्षा योग्य अभिलेखों सहित अलग खाता बहियां रखनी होंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय के लिए निर्धारित 100 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों का न्यूनतम शेष हमेशा रखा जाता है।
- (ii) बैंक-प्राथमिक व्यापारियों को प्राथमिक व्यापारी विभाग द्वारा किए गए लेनदेनों की समवर्ती लेखापरीक्षा करानी होगी। लेखा-परीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाए कि प्राथमिक व्यापारी बही में सरकारी प्रतिभूतियों का 100 करोड़ रुपयों का न्यूनतम निर्धारित शेष निरंतर आधार पर रखा गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों / अनुदेशों का पालन किया गया है।



## 10. हामीदारी गतिविधियां

मर्चेट बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में निर्गमों की हामीदारी करते समय बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण एकसपोजर सीमाओं के साथ-साथ बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, की धारा 19(2) और (3) में निहित सांविधिक सीमाओं का कड़ाई से पालन किया गया है। इसके अलावा, ऐसा कारोबार करते समय, बैंकों तथा उनकी मर्चेट बैंकिंग सहायक कंपनियों को भी सेबी के संगत विनियमनों का अनुपालन भी करना होगा।

## 11. सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री

बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, यथा लागू, के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-बैंक ग्राहकों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री का कारोबार करने की अनुमति दी जाती है:

- (i) बैंक, बिक्री और खरीद के बीच की अवधि में किसी भी प्रतिबंध के बिना मौजूदा बाजार कीमतों पर एकमुश्त आधार पर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।
- (ii) बैंकों को गैर बैंक ग्राहकों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों में तैयार वायदा लेनदेन का कार्य नहीं करना चाहिए।
- (iii) सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री द्वितीयक बाजार के लेनदेनों से उत्पन्न चालू बाजार दरों/प्रतिफल के आधार पर होना चाहिए।
- (iv) बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री तभी की जाएगी जब बैंक के पास अपने पोर्टफोलियो में भौतिक रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक में एसजीएल खाते में सरकारी प्रतिभूतियां मौजूद हो।
- (v) बिक्री के तुरंत बाद, संबंधित राशि बैंक द्वारा अपने निवेश खाते तथा एसएलआर आस्तियों से घटायी जानी चाहिए।
- (vi) बैंकों को इस संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण जाँच/प्रक्रिया लागू करनी चाहिए।
- (vii) यह लेनदेन भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा निर्देशों के अनुसार समवर्ती लेखा परीक्षा के अधीन किए होंगे और बैंक की सांविधिक लेखा परीक्षा के समय लेखा परीक्षकों द्वारा देखे जाने चाहिए।

## 12. पारस्परिक निधि (म्युच्युअल फंड) व्यवसाय

12.1 पारस्परिक निधि संबंधी व्यवसाय करने के लिए इच्छुक बैंकों को निम्नलिखित के अधीन फंड का गठन करने से पहले रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए:

- (i) बैंकों द्वारा प्रायोजित पारस्परिक निधियों को सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।
- (ii) बैंक द्वारा प्रायोजित पारस्परिक निधियों को अपने नाम के एक भाग के रूप में प्रायोजक बैंक के नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि प्रायोजक बैंक का नाम पारस्परिक निधि के साथ जोड़ा जाता है तो नई योजनाओं का प्रचार करते समय इस आशय का उपयुक्त दावा अधित्याग खंड जोड़ा जाना चाहिए कि इन योजनाओं के परिचालनों के परिणामस्वरूप यदि कोई हानि होती है या कमी आती है तो उसके लिए प्रायोजक बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

12.2 बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन पारस्परिक निधि की मार्केटिंग के लिए पारस्परिक निधियों के साथ करार कर सकते हैं:

- (i) बैंकों को एमएफ यूनिटों की खरीद/बिक्री के लिए निवेशकों से प्राप्त आवेदनों को म्युच्युअल फंडों/रजिस्ट्रारों/ट्रान्सफर एजेंटों को प्रेषित करते हुए केवल ग्राहकों के एजेंटों के रूप में कार्य करना चाहिए। यूनिटों की खरीद ग्राहक की जोखिम पर होनी चाहिए तथा किसी भी सुनिश्चित प्रतिफल की बैंक की गारंटी के बिना होनी चाहिए।
- (ii) बैंकों को पारस्परिक निधियों के यूनिट द्वितीयक बाज़ार से अर्जित नहीं करने चाहिए।
- (iii) बैंकों को अपने ग्राहकों से पारस्परिक निधियों के यूनिटों की पुनर्खरीद नहीं करनी चाहिए।
- (iv) यदि कोई बैंक पारस्परिक निधियों की यूनिटों की जमानत पर व्यक्तिगत ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव करते हैं तो ऐसी सुविधा की मंजूरी शेयरों/डिबेंचरों तथा म्युच्युअल फंडों की यूनिटों की जमानत पर अग्रिमों संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार होनी चाहिए।
- (v) अपने ग्राहकों की ओर से पारस्परिक निधि के यूनिटों को अभिरक्षा में रखनेवाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अपने निवेश और उनके ग्राहकों द्वारा किये गये निवेशों को एक दूसरे से अलग रखा जाए।
- (vi) बैंकों को इस संबंध में पर्याप्त और प्रभावी नियंत्रण प्रणाली लागू करनी चाहिए। इसके अलावा, बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पारस्परिक निधियों के यूनिटों की खुदरा बिक्री बैंक की विशिष्ट चयनित शाखाओं तक सीमित हो।

### 13. मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियां

मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियां सेबी के विनियमों के दायरे में आती हैं। अतः इस अतिरिक्त कार्यकलाप को प्रारंभ करने के लिए पंजीकरण हेतु सेबी से संपर्क करने से पहले मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियां स्थापित करने के इच्छुक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी।

### 14. पारस्परिक निधियों/मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों के निवेशकों को "चेक लिखने" की सुविधा

बैंक निम्नलिखित सुरक्षा मानदंडों के अधीन मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों और पारस्परिक निधियों के साथ गठजोड़ करके निवेशकों को चेक लिखने की सुविधा दे सकते हैं। इस प्रकार का गठजोड़ श्रेष्ठ प्रतिभूति निधियों और चलनिधि आय योजनाओं के संबंध में किया जा सकता है। ये निधियां मुख्यतः मुद्रा बाजार लिखतों में (कुल राशि का कम-से-कम 80 प्रतिशत) निवेश करती हैं :

- (i) बैंक द्वारा स्थापित मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि के मामले में गठजोड़ व्यवस्था प्रायोजक बैंक के साथ होनी चाहिए। अन्य मामलों में गठजोड़ नामित बैंक के साथ होना चाहिए। योजना के प्रस्ताव-दस्तावेज में बैंक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए।
- (ii) प्रस्ताव-दस्तावेज में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि "चेक लिखने की सुविधा" देने के लिए किया जाने वाला गठजोड़ केवल मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि /पारस्परिक निधि और नामित बैंक के बीच एक वाणिज्यिक व्यवस्था है और इसलिए मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि/पारस्परिक निधि की इकाइयों को सेवा प्रदान करना किसी भी स्थिति में संबंधित बैंक का प्रत्यक्ष दायित्व नहीं होगा। अतः सभी सार्वजनिक घोषणाओं में तथा व्यक्तिगत निवेशकों के साथ किये जाने वाले पत्राचार में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।
- (iii) मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि/पारस्परिक निधि के किसी एक निवेशक को उसके विकल्प पर नामित बैंक की शाखाओं में से किसी एक शाखा में यह सुविधा प्रदान की जा सकती है।
- (iv) यह आहरण खाते के रूप में होना चाहिए। यह किसी अन्य खाते से बिलकुल भिन्न होना चाहिए और आहरण, आहरित किये जानेवाले चेकों की संख्या आदि के संबंध में मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि/पारस्परिक निधि द्वारा यथानिर्धारित किये अनुसार स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए। नियमित बैंक खाते के रूप में इसका उपयोग नहीं होना

चाहिए और इस खाते पर आहरित चेक स्वयं निवेशक के पक्ष में (विमोचन के रूप में) होने चाहिए, किसी तीसरे पक्ष के नाम पर नहीं। खाते में कोई जमाराशि जमा नहीं की जा सकती। इस सुविधा के अंतर्गत निवेशक द्वारा किया गया प्रत्येक आहरण मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि/पारस्परिक निधि द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप होना चाहिए और इस सीमा तक मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि/पारस्परिक निधि में इन निधियों का विमोचन माना जाना चाहिए।

- (v) निवेशक इस सुविधा का लाभ मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि में किये गये निवेश के लिए कम-से-कम 15 दिन की निश्चित अवरुद्धता अवधि के बाद उठा सकते हैं। (यह शर्त पात्र श्रेष्ठ प्रतिभूति निधियों पर तथा पारस्परिक निधियों की चलनिधि आय योजनाओं पर लागू नहीं है। ऐसे मामलों में न्यूनतम निश्चित अवरुद्धता अवधि संबंधी निर्धारण सेबी विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे।)
- (vi) बैंकों को हर समय मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि/पारस्परिक निधि द्वारा आहरण खाते का पूर्व निधीयन सुनिश्चित करना चाहिए और निधि की स्थिति की समीक्षा दैनिक आधार पर की जानी चाहिए।
- (vii) ऐसे ही अन्य उपाय जिन्हें बैंक आवश्यक समझे।

## 15. बीमा व्यवसाय में बैंकों का प्रवेश

15.1 बैंक नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने की शर्तों के अधीन एक सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम स्थापित करके बीमा कारोबार कर सकते हैं तथा विभागीय रूप से या सहायक कंपनी के माध्यम से बीमा ब्रोकिंग/बीमा एजेंसी का कार्य कर सकते हैं। तथापि, यह नोट किया जाए कि संपूर्ण रूप में समूह ब्रोकिंग अथवा कार्पोरेट एजेंसी मोड के माध्यम से बीमा वितरण का कार्य कर सकता है अर्थात् समूह के भीतर, बीमा वितरण के लिए निर्धारित माडल समूह की कितनी भी संस्थाओं द्वारा अपनाया जा सकता है।

*(i) जोखिम सहभागिता के साथ बीमा कारोबार करने के लिए सहायक कंपनी संयुक्त उद्यम/स्थापित करने वाले बैंक*

बैंकों को विभागीय रूप से जोखिम सहभागिता के साथ बीमा कारोबार करने की अनुमति नहीं है तथा वे केवल इस प्रयोजन के लिए स्थापित सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम के माध्यम से ही ऐसा कर सकते हैं। नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों (पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार) को पूरा करनेवाले बैंक जोखिम सहभागिता के साथ बीमा कारोबार करने के लिए सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं :

- (क) बैंक की निवल मालियत 1000 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए ;

- (ख) बैंक का जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ;
- (ग) अनर्जक आस्तियों का स्तर 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ;
- (घ) बैंक ने लगातार पिछले तीन वर्षों में निवल लाभ कमाया हो; और
- (ङ) संबंधित बैंक की सहायक कंपनियों, यदि कोई हों, के कार्यनिष्पादन का पिछला रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन देते समय, बैंक के क्रियाकलापों, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन आदि के विभिन्न पहलुओं में विनियामक और पर्यवेक्षी सहजता को भी विचार में लिया जाएगा।

यह नोट किया जाए कि सामान्यतः किसी एक बैंक की सहायक कंपनी और किसी अन्य बैंक को जोखिम सहभागिता आधार पर बीमा कंपनी की इक्विटी में अंशदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बीमा कारोबार में निहित जोखिम बैंक को अंतरित नहीं किए जाते हैं और यह कि बीमा कारोबार से उत्पन्न जोखिमों से बैंकिंग कारोबार संक्रमित नहीं होता है। बैंक और बीमा संस्थान के बीच संबंध 'उचित दूरी' का होना चाहिए।

*(ii) सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम के माध्यम से बीमा ब्रोकिंग/कॉर्पोरेट एजेंसी का कार्य करने वाले बैंक*

बैंकों को सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेना आवश्यक होगा। तदनुसार, बीमा ब्रोकिंग/कॉर्पोरेट एजेंसी के लिए सहायक कंपनी की स्थापना करने के इच्छुक तथा नीचे दिए गए पात्रता मानदंडों (पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार) को पूरा करने वाले बैंक ऐसी सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु अनुमोदन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं:

- (क) ऐसी कंपनी में निवेश करने के बाद बैंक की निवल मालियत 500 करोड़ रुपये से कम न हो,
- (ख) बैंक का सीआरएआर 10 प्रतिशत से कम न हो;
- (ग) निवल अनर्जक आस्तियों का स्तर 3 प्रतिशत से अधिक न हो;
- (घ) बैंक ने पिछले तीन वर्षों में लगातार निवल लाभ अर्जित किया हो;
- (ङ) संबंधित बैंक की सहायक कंपनियों, यदि कोई हों, के कार्यनिष्पादन का पिछला रिकॉर्ड संतोषजनक हो।

अब तक की तरह, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदन देते समय बैंक के क्रियाकलापों, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जोखिम प्रबंधन आदि के विभिन्न पहलुओं में विनियामक और पर्यवेक्षी सहजता को भी विचार में लिया जाएगा।

सहायक कंपनी के माध्यम से कॉर्पोरेट एजेंट/ब्रोकर के रूप में बीमा वितरण शुरू करने का इरादा रखने वाले बैंक एक सहायक कंपनी के माध्यम से अनुबंध 3 में दी गई शर्तों के अधीन ऐसा कर सकते हैं।

**(iii) विभागीय रूप से कॉर्पोरेट एजेंसी क्रियाकलाप/ ब्रोकिंग कार्य करने वाले बैंक**

बैंकों को शुल्क के आधार पर कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में जोखिम सहभागिता के बिना/विभागीय रूप से बीमा ब्रोकिंग कार्यकलाप करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि आईआरडीए विनियमावली, तथा अनुबंध 3 में दी गई शर्तों का अनुपालन किया गया हो।

**(iv) बीमा सिफारिशी सेवाएं देने वाले बैंक**

आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण हेतु डेटाबेस शेयर करना) विनियमावली, 2010 के अनुसार वर्तमान में कोई भी बैंक बीमा सिफारिशी कारोबार करने के लिए पात्र नहीं है।

**16. बैंकों द्वारा पेंशन निधि प्रबंधन**

भारत सरकार की 24 मई 2007 की अधिसूचना एफ.सं.13/6/2005-बीओए के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कोई भी बैंकिंग कंपनी विधिक रूप से "पेंशन निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करने" का व्यवसाय कर सकती है। इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप बैंकों को सूचित किया गया है कि वे उक्त प्रयोजन से स्थापित सहायक कंपनियों के माध्यम से, भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन लेकर पेंशन निधि प्रबंधन कर सकते हैं तथा यह उनके द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए निर्धारित पात्रता के मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगा। पेंशन निधि प्रबंधन विभागीय तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। अनुबंध-4 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार पेंशन निधि प्रबंधन का कार्य प्रारंभ करने का इरादा रखने वाले बैंकों को ऐसे व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए अपेक्षित आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें सहायक कंपनी में किए जानेवाले प्रस्तावित ईक्विटी अंशदान के ब्यौरों सहित अनुबंध-4 में निर्धारित किए गए पात्रता के विभिन्न मानदंडों से

संबंधित पूर्ण जानकारी दी गई हो। इस संबंध में तैयार की गई विस्तृत अर्थक्षमता रिपोर्ट सहित इस संबंध में बोर्ड को प्रस्तुत नोट तथा उस पर पारित संकल्प जिसके जरिए बैंक के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया है भी रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाए।

## 17. सिफारिशी सेवाएं

बैंकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों के लिए सिफारिशी सेवाएं प्रदान किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है:

- (क) बैंक/वित्तीय उत्पादों के अन्य पक्षीय जारीकर्ता को चाहिए कि जिन ग्राहकों को उत्पादों के अन्य पक्षीय जारीकर्ता के पास भेजा जा रहा है, उनके मामले में वे अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल) दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
- (ख) संबंधित बैंक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वित्तीय उत्पादों के अन्य पक्षीय जारीकर्ता का चयन इस प्रकार किया जाता है कि उसमें उत्पादों के अन्य पक्षीय जारीकर्ता के साथ व्यवहार करने में बैंक को जिस प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम का सामना करना पड़ सकता है उसका पूरा ध्यान रखा गया हो।
- (ग) बैंक को चाहिए कि वह ग्राहक को पहले ही पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि वे पूर्णतः परामर्शी सेवा प्रदान कर रहे हैं जो पूर्णतः जोखिमेतर सहभागिता आधार पर है।
- (घ) अन्य पक्षीय जारीकर्ता को उन पर लागू संगत विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
- (ङ) सिफारिशी सेवाएं प्रस्तावित करते समय बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

## 18. सेबी अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार/सदस्यता

18 1. भारत के बैंकों तथा भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को अपने अंतर्निहित निवेश पोर्टफोलियो में जोखिम की हेजिंग के साथ ही ब्याज दर फ्यूचर्स (आइआरएफएस) में व्यापार पोजीशन के प्रयोजन से ब्याज दर फ्यूचर्स में कारोबार करने की अनुमति दी गयी है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है बैंकों को आइआरएफएस में ग्राहकों की ओर से लेनदेन का कार्य करने की अनुमति नहीं है। इस संदर्भ में, बैंकों को सूचित किया गया है कि वे समय-समय पर संशोधित नॉन आप्शन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हेतु सीमा तय करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

18.2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एडी संवर्ग 1) को यह अनुमति दी गई है कि वे सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में स्थापित किए जाने वाले करेंसी डेरिवेटिव खंड के ट्रेडिंग/ क्लियरिंग सदस्य बन सकते हैं, बशर्ते वे निम्नलिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाएं पूरी करते हों :

- (क) न्यूनतम निवल मालियत 500 करोड़ रुपए
- (ख) न्यूनतम सीआरएआर 10 प्रतिशत
- (ग) निवल एनपीए 3 प्रतिशत से अधिक नहीं, और
- (घ) पिछले तीन वर्षों में निवल लाभ

जो बैंक उपर्युक्त शर्तें पूरी करते हैं उन्हें इस गतिविधि के संचालन और जोखिम प्रबंध के लिए अपने बोर्ड के अनुमोदन से विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित करने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बैंक की पोजिशन ग्राहकों की पोजिशन से अलग रखी जाती है। यदि बैंक के कार्यकलाप के संबंध में पर्यवेक्षीय असंतोष हो तो रिजर्व बैंक इस कारोबार के संबंध में बैंक पर यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है।

जो बैंक उपर्युक्त न्यूनतम विवेकपूर्ण अपेक्षा पूरी नहीं करते हैं उन्हें केवल ग्राहक के रूप में करेंसी डेरिवेटिव मार्केट में भाग लेने की अनुमति दी जाती है।

18.3. भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में स्वपूंजी (प्रोप्राइटी) लेनदेन करने के प्रयोजन से सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों की सदस्यता लेने की अनुमति दी गयी है। ऐसा करते समय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को स्टॉक एक्सचेंजों की सदस्यता मानदंडों को पूरा करना होगा और सेबी तथा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों का पालन करना होगा।

## 19. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ

19.1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के अंतर्गत जमाराशि / निधि स्वीकार करने पर 7 जून 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी.95-94/27.07.001/73 के माध्यम से पोर्टफोलियो सेवाएं तथा इस प्रकार की योजनाएं परिचालित करने की बैंकों के पास निहित शक्तियों को वापस ले लिया गया है। अतः किसी भी बैंक को भविष्य में किसी भी नए पीएमएस या इसी तरह की योजना को भारतीय रिजर्व बैंक की विशिष्ट पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना पुनः आरंभ नहीं करना चाहिए। बैंक द्वारा प्रायोजित एनबीएफसी मामला-दर-मामला आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेकर अपने ग्राहकों के लिए विवेकाधीन पीएमएस का प्रस्ताव कर सकती हैं।



19.2 भारतीय रिजर्व बैंक के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के साथ पीएमएस या उसी प्रकार की योजनाएं परिचालित करने वाले बैंकों को निम्न शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा:

- (क) केवल उन बैंकों को यह गतिविधि शुरू करनी चाहिए जो स्वतः ऐसी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अपने ग्राहकों से पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए ली गयी राशि, प्रबंधन के लिए अन्य बैंक को सौंपी नहीं जानी चाहिए।
- (ख) 'पीएमएस', सीधे या परोक्ष रूप से पूर्व निर्धारित वापसी की गारंटी के बिना निवेश परामर्श / प्रबंधन के रूप में सशुल्क सेवा होनी चाहिए जो पूरी तरह से ग्राहक के जोखिम पर है। बैंक को चाहिए कि प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए एक निश्चित शुल्क ले, चाहे ग्राहक को मिलने वाला लाभ कुछ भी हो।
- (ग) बैंकों /उनकी सहायक कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घकालिक निवेश निधि के लिए प्रतिभूतियों का पोर्टफोलियो बनाने हेतु पीएमएस सेवा दी जाए, किसी भी स्थिति में एक वर्ष से कम अवधि के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए राशि न स्वीकारी जाए। निरंतर आधार पर एक से अधिक अवसर पर एक ही ग्राहक द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए राशि दिए जाने पर, इस तरह प्रत्येक निधि को एक अलग खाते के रूप में समझा जाना चाहिए और यह राशि न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए।
- (घ) पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए स्वीकार की गयी राशि का अनिवार्य रूप से शेयर, डिबेंचर, बांड, प्रतिभूतियों, आदि पूंजी बाजार लिखतों में निवेश करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में पोर्टफोलियो फंड कॉल मनी / बिल बाजार में ऋण देने के लिए तथा कॉरपोरेट निकायों को उधार के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए।
- (ङ) अपने ग्राहकों को पीएमएस सुविधा देने वाले बैंक को स्वीकार की गयी निधि और उनके निवेश का ग्राहक वार खाता/ रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए और सभी क्रेडिट (प्राप्त ब्याज, लाभांश, आदि सहित) और पोर्टफोलियो के खाते से संबंधित डेबिट इस प्रकार के खाते के माध्यम से ही होना चाहिए। पोर्टफोलियो खाते में रखी प्रतिभूतियों पर ब्याज / लाभांश के संबंध में स्रोत पर कर कटौती पोर्टफोलियो खाते में दर्शायी जानी चाहिए। खाता धारक अपने पोर्टफोलियो खाते का विवरण प्राप्त करने का हकदार होना चाहिए।
- (च) पीएमएस ग्राहकों से संबंधित निवेश और बैंक का अपना निवेश एक दूसरे से अलग रखा जाना चाहिए। बैंक के निवेश खाते और पोर्टफोलियो खाते के बीच कोई भी लेनदेन किया जाता है तो वह अनिवार्यतः बाजार दरों पर किया जाना चाहिए। यद्यपि बैंक अपने पीएमएस ग्राहकों की ओर से अपने नाम में पोर्टफोलियो के खाते से संबंधित प्रतिभूतियाँ रख सकता है, तथापि यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि प्रतिभूतियाँ को पोर्टफोलियो खाते की ओर से रखा गया है। इसी तरह,

पोर्टफोलियो खाते की ओर से कोई भी लेन - देन करने पर स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए कि लेन - देन 'पोर्टफोलियो खाता' से संबंधित है।

- (छ) बैंक की प्रधान खाताबही में 'ग्राहक पोर्टफोलियो खाता' रखा जाना चाहिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए खाते में प्राप्त राशि दैनिक आधार पर उस में परिलक्षित होनी चाहिए। इस खाते की शेष राशि (अर्थात् इस खाते की निवेश न की गयी राशि, यदि कोई हो) बैंक के बाहर से उधार के रूप में समझा जाना चाहिए और बैंक को इस प्रकार की निधि पर सीआरआर/ एसएलआर बनाए रखना चाहिए। पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए बैंक द्वारा प्राप्त निधियों के लिए अपने ग्राहकों के प्रति बैंक की देयता बैंक / सहायक कंपनी के प्रकाशित लेखा में दर्शायी जानी चाहिए।
- (ज) व्यापार तथा बैंकों के अपने निवेश खाते से संबंधित बैंक ऑफिस कार्य तथा पीएमएस के बीच स्पष्ट कार्यात्मक अलगाव होना चाहिए।
- (झ) बैंकों को पीएमएस ग्राहकों के खातों की बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा एक अलग लेखा परीक्षा करानी चाहिए जैसा कि (20 जून 1992 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीसी. 143 ए/24.048.008/91-9 92-91/पैरा.3 ॥ (I) में उल्लिखित है।)
- (ञ) बैंक यह ध्यान में रखे कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा। उल्लंघन होने पर पीएमएस गतिविधि पर रोक लगाने के साथ-साथ आरक्षित निधि अपेक्षा को बढ़ाना, भारतीय रिजर्व बैंक से पुनर्वित्त की सुविधा हटाना तथा मुद्रा बाजार में प्रवेश न देना जैसी निवारक कार्रवाई बैंकों के खिलाफ की जाएगी।
- (ट) इसके अलावा, उक्त निर्देश बैंकों की सहायक कंपनियों पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू रहेंगे सिवाय उन स्थितियों के जहां वे उनके परिचालन पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक या सेबी के विनिर्दिष्ट विनियमों के विपरीत हैं।
- (ठ) बैंक/बैंकों की मर्चेन्ट बैंकिंग सहायक कंपनियां जो भारतीय रिजर्व बैंक के विशिष्ट पूर्व अनुमोदन के साथ पीएमएस या उसी प्रकार की अन्य योजनाएं परिचालित करती हैं, को समय-समय पर जारी, सेबी (पोर्टफोलियो प्रबंधक) नियम और विनियम 1993 में निहित दिशानिर्देशों का पालन भी करना होगा।

## 20. सेफ्टी नेट योजनाएं

20.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने यह पाया है कि कुछ बैंक/उनकी सहयोगी कंपनियां अपने मर्चेन्ट बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में 'सेफ्टी नेट' योजना के नाम से कुछ सार्वजनिक निर्गमों से संबंधित वापसी खरीद (बाय बैक) सुविधाएं प्रदान करती हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत मूल निवेशकों से संबंधित प्रतिभूतियाँ नियत अवधि के दौरान किसी भी समय, भले ही प्रचलित बाजार मूल्य कुछ भी हो, निर्गम के समय निर्धारित किये गये मूल्य पर खरीदने की प्रतिबद्धता के रूप में बड़े एक्सपोजर लिये जाते हैं। कुछ मामलों में जिन कंपनियों के निर्गमों का इन

योजनाओं के अंतर्गत समर्थन किया गया था, उनसे किसी प्रकार के औपचारिक अनुरोध के बिना ही ऐसी योजनाएं बैंकों ने अपने आप प्रस्तावित की थीं। स्पष्टतः ऐसे मामलों में निर्गमकर्ताओं द्वारा प्रतिभूतियां खरीदने संबंधी कोई वचन नहीं दिया गया था। इन योजनाओं में निहित हानि के जोखिम के अनुरूप कोई आय नहीं थी, क्योंकि जब प्रतिभूतियों का बाजार- मूल्य पूर्व निर्धारित मूल्य से कम होता है, केवल तब ही निवेशक इन योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित सुविधाओं का आश्रय लेगा। इसलिए बैंक/ उनकी सहायक कंपनियों को सूचित किया गया है कि इस प्रकार की 'सेफ्टी नेट' सुविधाएं प्रस्तावित न करें, चाहे जिस नाम से भी उन्हें संबोधित किया जाये।

20.2 कुछ मामलों में, निर्गमकर्ता उनके द्वारा जारी ऋणपत्रों के लिए चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए मूल निवेशकों को एक वर्ष की अवरुद्धता अवधि के बाद गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्रों के संबंध में 40,000 रुपए तक की वापसी खरीद की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। यदि, निर्गमकर्ता के अनुरोध पर, बैंक अथवा उनकी सहायक कंपनियां नए निर्गमों में अभिदान करने वाले छोटे निवेशकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना जरूरी समझते हैं, तो ऐसी वापसी खरीद व्यवस्था में पूर्व-निर्धारित कीमतों पर प्रतिभूतियों की खरीद प्रतिबद्धताएं शामिल नहीं होनी चाहिए। कीमतों का निर्धारण समय-समय पर प्रतिभूतियों की शेयर बाजार में मौजूदा कीमत को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। प्रतिबद्धताएं, राशि के अर्थों में भी, कुल निर्गम के संयत अनुपात तक ही सीमित रहनी चाहिए और यह बैंक/उसकी सहायक कंपनी की स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उक्त प्रतिबद्धताएं समय समय पर निर्धारित/ निर्धारित की जाने वाली समग्र सीमाओं के भी अधीन होंगी।

## 21. शुल्क/पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

21.1 इस परिपत्र के पैरा 12 के अनुसार बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे कुछ शर्तों के अधीन म्यूचुअल फंड यूनिटों के विपणन के लिए म्यूचुअल फंडों के साथ करार कर सकते हैं।

साथ ही, इस परिपत्र के पैराग्राफ 15 के अनुसार बैंकों को यह सूचित किया गया है कि उन्हें उक्त मास्टर परिपत्र के अनुबंध 3 में निर्धारित शर्तों के अधीन बीमा एजेंसी व्यवसाय अथवा ब्रोकिंग व्यवस्था में संलग्न होने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। बैंकों को इस परिपत्र के पैराग्राफ 17 द्वारा यह भी अनुमति दी गयी है कि वे कतिपय शर्तों के अधीन वित्तीय उत्पादों के लिए अपने ग्राहकों को गैर-जोखिम सहभागिता के आधार पर विशुद्ध सिफारिशी सेवाएं दे सकते हैं। उपर्युक्त के अलावा, बैंक अपने ग्राहकों को गैर विवेकाधीन

निवेश परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करते हैं जिनके लिए प्रत्येक मामले के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

21.2 साथ ही, कुछ मामलों में बैंकों को अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से कुछ शर्तों के अधीन विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंध सेवाएं प्रदान करने की अनुमति भी दी गयी है। ऊपर संदर्भित सभी गतिविधियों में यह संभावित है कि बैंक विभिन्न म्यूचुअल फंडों/बीमा/वित्तीय कंपनियों के कई प्रतिस्पर्धी उत्पादों की अपने ग्राहकों को बिक्री/सिफारशी सेवाएं प्रदान करें।

जिन ग्राहकों को उत्पाद बेचे या सिफारिश किये जा रहे हैं उनके हित में पारदर्शिता की आवश्यकता को देखते हुए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने ग्राहकों को ऐसे कमीशन/अन्य शुल्क (किसी भी रूप में प्राप्त) के ब्योरे बताएं जो उन्हें विभिन्न म्यूचुअल फंडों/बीमा/अन्य वित्तीय कंपनियों से उनके उत्पादों के विपणन/सिफारिश के लिए प्राप्त होते हैं।

यह प्रकटीकरण ऐसे मामलों में भी अपेक्षित है जहाँ बैंक केवल एक म्यूचुअल फंड/बीमा कंपनी आदि के उत्पादों का विपणन/वितरण कर रहे हैं/सिफारिश सेवाएं दे रहे हैं।

21.3 बैंकों के वित्तीय विवरणों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर परिपत्र जारी करके बैंकों से यह अपेक्षा की है कि वे अपने तुलन-पत्र के 'लेखे पर टिप्पणियां' के अंतर्गत प्रकटीकरण करें। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक और कदम के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि बैंक 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष से 'लेखे पर टिप्पणियां' में उनके द्वारा किए गए बैंकएशयोरेंस कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क/पारिश्रमिक के ब्योरों का प्रकटीकरण करें।

## वित्तीय सेवा कंपनियां

सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों में निवेश पर विवेकपूर्व दिशानिदेशों के प्रयोजन के लिए 'वित्तीय सेवा कंपनियों' से तात्पर्य 'वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय' से जुड़ी कंपनियों से है। 'वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय' से तात्पर्य है -

- (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (क), (ग), (घ), (ड.) के तहत यथावर्णित तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ण) के तहत अधिसूचित प्रकार के कारोबार;
- (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक, 1934 की धारा 45 के खंड (ग) तथा खंड (च) के तहत यथावर्णित प्रकार के कारोबार;
- (iii) ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के तहत यथावर्णित ऋण सूचना का कारोबार;
- (iv) भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत यथापरिभाषित किसी भुगतान प्रणाली का प्रचालन;
- (v) शेयर बाजार, पण्य बाजार, डेरिवेटिव बाजार या इसी प्रकार के अन्य बाजार के परिचालन ;
- (vi) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के तहत यथावर्णित निक्षेपागार के परिचालन;
- (vii) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत यथावर्णित प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण कंपनी का कारोबार;
- (viii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत यथावर्णित मर्चेट बैंकर, पोर्टफोलियो प्रबंधक, शेयर दलाल, उप-दलाल, शेयर अंतरण एजेंट, न्यास विलेख का न्यासी, किसी इश्यू का पंजीयक, मर्चेट बैंकर, हामीदार, डिबेंचर न्यासी, निवेश परामर्शदाता तथा इसी प्रकार के अन्य मध्यस्थ का कारोबार ;

- (ix) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण निर्धारक एजेंसी) विनियमावली 1999 के तहत यथापरिभाषित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कारोबार;
- (x) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत दी गयी परिभाषा के अनुसार सामूहिक निवेश योजना का कारोबार ;
- (xi) पेंशन निधि प्रबंध का कारोबार ;
- (xii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत दी गयी परिभाषा के अनुसार प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था का कारोबार;
- (xiii) रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य कारोबार ।

**भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी, संयुक्त उद्यम, 'नियंत्रण और महत्वपूर्ण प्रभाव' की परिभाषा**

लेखांकन मानक 18, 21, 23 और 27 उपर्युक्त शब्दों को परिभाषित करते हैं ।

**सहायक कंपनी** वह उद्यम है जो किसी अन्य उद्यम (जिसे मूल या प्रवर्तक उद्यम कहा जाता है) द्वारा नियंत्रित हो ।

**सहयोगी कंपनी** वह उद्यम है जिसमें निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव हो और जो निवेशक की न तो सहायक कंपनी हो और न ही संयुक्त उद्यम, और

**संयुक्त उद्यम** एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा दो या अधिक पक्षकार कोई आर्थिक गतिविधि आरंभ करते हैं, जो संयुक्त नियंत्रण के अधीन हो ।

**महत्वपूर्ण प्रभाव** निवेशिती के वित्तीय और/अथवा परिचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी करने लेकिन इसकी नीतियों को नियंत्रित नहीं करने की शक्ति है ।

**नियंत्रण -**

(क) किसी उद्यम के आधे से अधिक मताधिकार पर प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः सहायक उद्यम (उद्यमों) के माध्यम से स्वामित्व रखना; अथवा

(ख) किसी कंपनी के मामले में निदेशक बोर्ड के गठन पर नियंत्रण अथवा किसी अन्य उद्यम के मामले में तदनु रूप नियंत्रक निकाय के गठन पर नियंत्रण ताकि उसकी गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके ।

नियंत्रण तब माना जाता है जब मूल या प्रवर्तक उद्यम, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः सहायक संस्था/(ओं) के माध्यम से किसी उद्यम के मताधिकार के आधे से अधिक अंश पर स्वामित्व रखता है। नियंत्रण तब भी माना जाता है जब कोई उद्यम, निदेशक बोर्ड (किसी कंपनी के मामले में) अथवा तदनु रूप नियंत्रक निकाय (यदि उद्यम कंपनी नहीं हो) के गठन को नियंत्रित करता है, ताकि उसकी गतिविधियों से आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड के गठन पर किसी उद्यम का नियंत्रण तब माना जाता है जब उस उद्यम के पास किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की सहमति लिये बिना कंपनी के सभी या बहुसंख्यक निदेशकों को नियुक्त करने या हटाने की शक्ति हो। किसी उद्यम के पास कोई

निदेशक नियुक्त करने की शक्ति, यदि कोई हो, तब मानी जाती है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हों:

- (क) कोई व्यक्ति तब तक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं हो सकता जब तक कि उसके पक्ष में उपर दिए गए अधिकार का उक्त उद्यम द्वारा प्रयोग न किया जाए; अथवा
- (ख) उक्त उद्यम में किसी पद पर नियुक्ति के साथ ही अनिवार्य रूप से वह व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त हो जाता है; अथवा
- (ग) निदेशक उस उद्यम द्वारा नामित होता है; यदि वह उद्यम कंपनी हो तो निदेशक उस कंपनी/सहायक कंपनी द्वारा नामित हो ।

एस 23 के प्रयोजन से, महत्वपूर्ण प्रभाव के अंतर्गत किसी उद्यम की वित्तीय और/अथवा परिचालन नीतियों को नियंत्रित करना शामिल नहीं है । महत्वपूर्ण प्रभाव शेयर के स्वामित्व, संविधि या करार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । जहां तक शेयर स्वामित्व का संबंध है, यदि कोई निवेशक निवेशिती के मताधिकार का 20% या उससे अधिक अंश प्रत्यक्षतः या सहायक उद्यम (उद्यमों) के माध्यम से अप्रत्यक्षतः धारित करता है, तो यह माना जाता है कि निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव है - केवल उस स्थिति में नहीं, जब यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके कि ऐसी बात नहीं है। ठीक इसके विपरीत, यदि कोई निवेशक किसी निवेशिती में मताधिकार का 20% से कम अंश प्रत्यक्षतः अथवा सहायक उद्यम (उद्यमों) के माध्यम से अप्रत्यक्षतः धारित करता है तो यह माना जाता है कि निवेशक के पास महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है - केवल उस स्थिति में नहीं जब ऐसा प्रभाव स्पष्ट रूप में दर्शाया जा सके । किसी अन्य निवेशक का महत्वपूर्ण या प्रमुख स्वामित्व हो तो इससे निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव बाधित हो जाए यह आवश्यक नहीं है । किसी निवेशक का महत्वपूर्ण प्रभाव निम्नलिखित एक या अधिक तरीकों से प्रमाणित होता है :

- (क) निवेशिती के निदेशक बोर्ड या तदनु रूप नियंत्रक निकाय में प्रतिनिधित्व;
- (ख) नीति निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता;
- (ग) निवेशक या निवेशिती के बीच में महत्वपूर्ण लेनदेन;
- (घ) प्रबंधकीय कार्मिकों का आदान-प्रदान; और
- (ङ) आवश्यक तकनीकी सूचना की व्यवस्था ।



### बीमा ब्रोकिंग और एजेंसी कारोबार करने वाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश

बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन विभागीय और/अथवा सहायक संस्था के माध्यम से बीमा एजेंसी अथवा ब्रोकिंग का कारोबार कर सकते हैं :

#### 1. निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति

बीमा वितरण कारोबार, चाहे यह एजेंसी के रूप में हो या ब्रोकिंग माडल के रूप में, प्रारंभ करने के लिए निदेशक मंडल के अनुमोदन से एक व्यापक नीति तैयार की जानी चाहिए तथा इसी नीति के अनुसार ग्राहकों को सेवाओं की पेशकश की जानी चाहिए। उक्त नीति में ग्राहक औचित्य तथा उपयुक्तता के मुद्दों के साथ-साथ शिकायत निवारण को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के दिशानिर्देश समूह की संस्थाओं को उसी समूह में, यहां तक कि अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से भी, कार्पोरेट एजेंसी लेने और ब्रोकिंग की अनुमति नहीं देते हैं, बैंक और उनके समूह की संस्थाएं या तो बीमा ब्रोकिंग या फिर कार्पोरेट एजेंसी का कारोबार कर सकते हैं।

#### 2. आईआरडीए के दिशा निर्देशों का अनुपालन

क) ऐसा कारोबार करने वाले बैंकों को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (कार्पोरेट एजेंटों को लाइसेंस दिया जाना) विनियमन, 2002/बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बैंकों को बीमा ब्रोकरों के रूप में लाइसेंस दिया जाना) विनियमन, 2013 तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आचार संहिता, समय-समय पर संशोधित, यथा लागू का अनुपालन करना होगा।

ख) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बैंकों को बीमा ब्रोकरों के रूप में लाइसेंस दिया जाना) विनियमन, 2013, समय-समय पर संशोधित, के अनुसार बीमा ब्रोकर के रूप में रखी जाने वाली जमाराशि अपने अलावा किसी अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में रखनी होगी।

#### 3. ग्राहक औचित्य और उपयुक्तता सुनिश्चित करना

संबंधित आईआरडीए विनियमों के तहत एजेंसी के रूप में अथवा ब्रोकिंग मॉडल के रूप में बीमा वितरण कारोबार करते समय बैंकों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा :

क) बीमा एजेंसी/ब्रोकिंग कारोबार से जुड़े सभी कर्मचारियों के पास आईआरडीए द्वारा निर्धारित अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए।

ख) ग्राहकों के लिए उत्पादों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किए जाने की प्रणाली होनी चाहिए। निवेश अथवा वृद्धि घटक रहित विशुद्ध जोखिम आवधिक उत्पाद ग्राहक के लिए सरल और समझने में आसान होते हैं, इनको सर्वत्र उपयुक्त उत्पाद माना जा सकता है। निवेश घटक सहित अधिक जटिलता वाले उत्पादों के मामले में बैंक के लिए जरूरी होगा कि वे बिक्री से पहले ग्राहक की जरूरत का मूल्यांकन अवश्य कर लें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक की जरूरतों के मूल्यांकन हेतु एक मानक प्रणाली हो और इसमें शुरुआती/लेनदेन संबंधी और अनुमोदन की प्रक्रिया को अलग-अलग रखा गया हो।

ग) बेचे गए बीमा उत्पाद की उपयुक्तता और औचित्यता के संबंध में बैंक को अपने ग्राहकों के साथ उचित, इमानदार और पारदर्शी व्यवहार करना चाहिए।

#### **4. बैंक कर्मचारियों को सीधे ही कमीशन/प्रोत्साहन राशि के भुगतान की मनाही**

कमीशन/ब्रोकरेज/प्रोत्साहन राशि के भुगतान में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10(1)(ii) और आईआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसे स्टाफ के लिए यथोचित कार्य निष्पादन मूल्यांकन तथा प्रोत्साहन संरचना तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बीमा कंपनी द्वारा बीमा ब्रोकिंग/ कार्पोरेट एजेंसी सेवाओं से जुड़े स्टाफ को किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि (नकद या गैर-नकद) का भुगतान न किया जाए।

#### **5. केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन**

समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी, बैंकों पर लागू केवाईसी/एएमएल/सीएफटी से संबंधित अनुदेशों/दिशानिर्देशों को ऐसे ग्राहकों (दोनों मौजूदा तथा अकस्मात) जिनको बीमा ब्रोकिंग/एजेंसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, पर भी लागू किया जाना चाहिए।

#### **6. पारदर्शिता तथा प्रकटन**

क) बैंक को किसी खास बीमा कंपनी के उत्पाद का चयन करने हेतु ग्राहक पर दबाव डालने या बैंकिंग उत्पाद के साथ इस तरह के उत्पाद की बिक्री को संबद्ध करने जैसी किसी भी प्रतिबंधात्मक पद्धति को नहीं अपनाना चाहिए। बैंक द्वारा वितरित की जाने वाली समस्त प्रचार सामग्री में इस बात का प्रमुखता से उल्लेख किया जाना चाहिए कि बैंक के ग्राहक के लिए बीमा

उत्पादों की खरीद पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इसे बैंक से किसी भी अन्य सुविधा को प्राप्त करने से जोड़ा नहीं गया है।

ख) इसके अलावा, उनके द्वारा किए गए बीमा ब्रोकिंग/एजेंसी कारोबार से प्राप्त शुल्क/ब्रोकरेज के ब्योरे उनके तुलनपत्र के 'लेखों पर टिप्पणियां' शीर्ष के अंतर्गत प्रकट किए जाने चाहिए।

#### **7. ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली**

प्रदान की जा रही सेवाओं से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ग्राहक मुआवजा नीति के साथ-साथ एक सुदृढ आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिन बीमा कंपनियों के उत्पाद बेचे जा रहे हैं उनके यहां भी सुदृढ ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली लागू की गई हो। इसके अलावा, बैंक को शिकायतों के निवारण में सहयोग करना चाहिए।

#### **8. दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई**

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए बैंकों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

पेंशन निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश

1. पात्रता के मानदंड

बैंकों को केवल अपनी सहायक संस्थाओं के माध्यम से पेंशन निधि प्रबंधन (पीएफएम) का कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। पेंशन निधि प्रबंधन का कार्य विभागीय तौर पर नहीं किया जाएगा। बैंक पेंशन निधि प्रबंधन के लिए बनाई गई अपनी सहायक संस्थाओं को अपने नाम/संक्षेपाक्षर दे सकते हैं ताकि उनके ब्रैंड नाम तथा उससे संबद्ध लाभों का फायदा हो सके बशर्ते वे सहायक संस्थाओं के साथ समुचित दूरी का संबंध रखें। संबद्ध जोखिमों के प्रति पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल सुदृढ तथा विश्वसनीय बैंक ही पेंशन निधि प्रबंधन के व्यवसाय में प्रवेश कर सकें, निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले (पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित शोधक्षमता मार्जिन का अनुपालन भी करने वाले) बैंक, पेंशन निधि प्रबंधन के व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क कर सकते हैं:

(क) बैंक की निवल मालियत 500 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान बैंक का सीआरएआर 11 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

(ग) बैंक पिछले लगातार तीन वर्षों से निवल लाभ कमा रहा हो।

(घ) परिसंपत्ति पर आय (आरओए) कम-से-कम 0.6 प्रतिशत अथवा उससे अधिक होनी चाहिए।

(ङ) निवल अनर्जक परिसंपत्तियों का स्तर 3 प्रतिशत से कम होना चाहिए।

(च) बैंक की यदि कोई सहायक संस्था (संस्थाएं) हो, तो उनका कार्यनिष्पादन संतोषजनक होना चाहिए।

(छ) रिज़र्व बैंक की वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन अच्छा होना चाहिए और रिपोर्ट में पर्यवेक्षी बातों के संबंध में कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी (टिप्पणियां) नहीं होनी चाहिए।

## 2. पेंशन निधि सहायक कंपनी - रक्षोपाय

उपर्युक्त पात्रता मानदंडों तथा पेंशन निधि प्रबंधकों के लिए पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित मानदंडों को भी पूरा करनेवाले बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पेंशन निधि प्रबंधन के लिए सहायक संस्थाएं स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी:-

(क) सहायक संस्था स्थापित करने के प्रयोजन से ईक्विटी में निवेश करने के लिए बैंक को रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। सहायक संस्था में उसकी शेयरधारिता को अंतरित करने अथवा उससे अन्यथा किसी भी प्रकार का व्यवहार करने के लिए भी रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा।

(ख) सहायक संस्था के निदेशक बोर्ड की संरचना व्यापक आधार पर तथा पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुसार होनी चाहिए।

(ग) मूल बैंक को अपनी सहायक संस्था के साथ "समुचित दूरी" बनाए रखनी चाहिए। बैंक तथा उसकी सहायक संस्था के बीच कोई भी लेनदेन बाज़ार से संबंधित दरों पर होना चाहिए।

(घ) सहायक संस्था में बैंक द्वारा कोई भी अतिरिक्त ईक्विटी अंशदान रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से होगा और किसी भी समय सहायक संस्था में बैंक का कुल ईक्विटी अंशदान उसकी अपनी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होगा।

(ङ) बैंक की अपनी विद्यमान सहायक संस्थाओं, प्रस्तावित पेंशन निधि सहायक संस्था तथा अन्य वित्तीय सेवा तथा गैर वित्तीय संस्थाओं तथा म्यूच्युअल फंडों में पोर्टफोलियो निवेशों सहित भविष्य में बनने वाली सहायक संस्थाओं में ईक्विटी अंशदान के रूप में बैंक का कुल निवेश उसकी प्रदत्त पूंजी तथा आरक्षित निधियों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(च) मूल बैंक के बोर्ड को सहायक संस्था सहित संपूर्ण समूह के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति निर्धारित करनी चाहिए; जिसमें उचित जोखिम प्रबंधन साधनों को शामिल किया जाए। बैंक के बोर्ड को उसका प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करना चाहिए।

(छ) बैंक को सहायक संस्था के परिचालनों की निगरानी करने के लिए पर्याप्त प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

(ज) सहायक संस्था को अपने आप को पेंशन निधि प्रबंधन व्यवसाय तथा कोई अन्य व्यवसाय जो पूर्णतः प्रासंगिक तथा उससे प्रत्यक्ष संबंधित है तक सीमित रखना चाहिए।

(झ) पेंशन निधि सहायक संस्था को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना कोई अन्य सहायक संस्था स्थापित नहीं करनी चाहिए।

(ञ) सहायक संस्था को रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी नई कंपनी का प्रवर्तन नहीं करना चाहिए जो उसकी सहायक संस्था नहीं है।

(ट) सहायक संस्था को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना नियंत्रक हित अर्जित करने के उद्देश्य से किसी अन्य विद्यमान संस्था में पोर्टफोलियो निवेश नहीं करना चाहिए।

(ठ) बैंक को रिज़र्व बैंक को एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें पहले पांच वर्ष के लिए सहायक संस्था के व्यावसायिक अनुमानों का विशेष उल्लेख किया गया हो ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सहायक संस्था पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित शोधक्षमता मार्जिन का अनुपालन कर सकेगी अथवा नहीं और इस प्रयोजन से अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक पर निर्भर नहीं रहेगी।

(ड) सहायक संस्था स्थापित करने के लिए किसी बैंक को रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई अनुमति पीएफआरडीए के उक्त सहायक संस्था को पेंशन निधि प्रबंधन व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

(ढ) सहायक संस्था को पीएफआरडीए द्वारा पेंशन निधि प्रबंधन पर समय-समय पर जारी किए गए सभी अनुदेशों, दिशानिर्देशों आदि, का पालन करना चाहिए।

(ण) बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंक में रखे गए ग्राहकों के खातों तक सहायक संस्था की ऑन-लाइन पहुंच नहीं है।

(त) बैंक की प्रणालीगत अखंडता को बनाए रखने के लिए बैंक को चाहिए कि वह अपनी तथा सहायक संस्था की प्रणालियों के बीच पर्याप्त रक्षोपाय स्थापित करे।

(थ) जहां भी लागू हो वहां बैंक को "वित्तीय संगुट" ढांचे के अंतर्गत निर्धारित की गई रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

(द) बैंक को चाहिए कि वह रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना संयुक्त उद्यम अथवा सहायक संस्था को कोई भी गैर-जमानती अग्रिम प्रदान न करे।

\*\*\*\*\*

## मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	11.02.2015	बैंकों का बीमा कारोबार में प्रवेश
2.	<a href="#">आरबीआई/2014-15/409</a> <a href="#">बैंपविवि.सं.एफएसडी.बीसी.62/24.</a> <a href="#">01.018/2014-15</a>	15.01.2015	बैंकों का बीमा कारोबार में प्रवेश
3.	<a href="#">आरबीआई/2012-13/494</a> <a href="#">आइडीएमडीसं.पीडीआरडी..</a> <a href="#">_3089/03.64.027/2012-13</a>	08.05.2013	वचनपत्र प्रस्तुत करना - प्राधिकार का नवीनीकरण
4.	<a href="#">आरबीआई/2012-13/277</a> <a href="#">बैंपविवि.सं.एफएसडी.बीसी.53/2</a> <a href="#">4.01.001/2012-13</a>	05.11.2012	कारपोरेट बांड बाजार- सेबी द्वारा अनुमोदित शेयर बाजारों की सदस्यता के लिए बैंकों को अनुमति
5.	<a href="#">आरबीआई/2011-12/297</a> <a href="#">बैंपविवि.सं.एफएसडी.बीसी.62/2</a> <a href="#">4.01.001/2011-12</a>	12.12.2011	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 - सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों में अधिकतम निवेश सीमा
6.	आरबीआई/2011-12/269 बैंपविवि.सं.एफएसडी.बीसी.571/2 4.01.006/2011-12	21.11.2011	इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियों(आईडीएफ) के प्रायोजक के रूप में बैंक
7.	<a href="#">आरबीआई/2011-12/162</a> <a href="#">आइडीएमडीसं .पीसीडी.. 9</a> <a href="#">/14.03.05/2011-12</a>	30.08.2011	प्राथमिक व्यापारियों के लिए प्राधिकार दिशानिर्देश
8.	<a href="#">आरबीआई /2009-10/283</a> <a href="#">बैंपविवि.सं.एफएसडी.बीसी.67/</a> <a href="#">24.01.001/2009-10</a>	07.01.2010	तुलन-पत्र में प्रकटीकरण - बैंकेश्योरेंस कारोबार
9.	<a href="#">आरबीआई /2009-10/225</a> <a href="#">बैंपविवि.सं.एफएसडी.बीसी.60/</a> <a href="#">24.01.001/2009-10</a>	16.11.2009	म्यूचुअल फंड/बीमा आदि उत्पादों का बैंकों द्वारा विपणन/वितरण
10.	आरबीआई /2009-10/35 बैंपविवि. बीपी.बीसी. 60/ 24.01.001/2009-10	28.08.2009	एक्सचेंज ट्रेड ब्याज दर डेरिवेटिव
11.	आरबीआई /2008-9/217 बैंपविवि. बीपी.बीसी. 56/ 24.04.157/2009-10	13.10.2008	एक्सचेंज ट्रेड ब्याज दर डेरिवेटिव

12.	<a href="#">बैंपविवि.सं.एफएसडी.बीसी.29/ 24.01.001/2008-09</a>	06.08.2008	करेंसी फ्यूचर्स आरम्भ करना- सेबी द्वारा अनुमोदित एक्सचेंजों के ट्रेडिंग/क्लियरिंग सदस्य बनने के लिए बैंकों को अनुमति देना
13.	<a href="#">आरबीआई /2009-10/65 बैंपविवि.सं. एफएसडी. बीसी. 18/ 24.01.001/2009-10</a>	01.07.2009	पैरा बैंकिंग गतिविधियों पर मास्टर परिपत्र
14.	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	17.04.2008	शेयर और डिबेंचर का पब्लिक इश्यू- बैंक / सहायक कंपनियों द्वारा हामीदारी
15.	<a href="#">आरबीआई /2006-07/446 बैंपविवि.सं. एफएसडी. बीसी. 102/ 24.01.022/2006-07</a>	28.06.2007	बैंकों द्वारा पेंशन निधि प्रबंधन (पीएफएम)
16.	<a href="#">आरबीआई /2006-07/205 बैंपविवि.सं. एफएसडी. बीसी. 46/ 24.01.028/2006-07</a>	12.12.2006	संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वित्तीय विनियमन तथा उनके साथ बैंकों का संबंध- अंतिम दिशानिर्देश
17.	आरबीआई /2006-07/140 आइडीएमडी.पीडीआरएस.1431/ 03.64.00/2006-2007	05.10.2006	प्राथमिक व्यापारी व्यवसाय प्रारंभ करने वाले/प्रारंभ करने का प्रस्ताव करनेवाले बैंकों के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश
18.	आरबीआई /2006-7/113 बैंपविवि. बीपी.बीसी. 27/ 21.01.002/2009-10	23.08.2006	विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफ) में बैंकों का निवेश
19.	आरबीआई/ 2006-07/104 बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. सं.25/24.92.001/2006-07	09.08.2006	पीडी कारोबार शुरू करनेवाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश
20.	<a href="#">आरबीआई/ 2005-06/308 बैंपविवि. एफएसडी. बीसी. सं. 64 /24.92.001/2005-06</a>	27.02.2006	पीडी कारोबार शुरू करनेवाले बैंकों के लिए दिशानिर्देश
21.	आरबीआई/2004/260 बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 100/21.03.054/2003-04	21.06.2004	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य -बैंकों की ऋण जोखिम संबंधी विवेकपूर्ण सीमाएं
22.	बैंपविवि. सं. एफएसडी. बीसी. 66/ 24.01.002/ 2002-03	31.01.2003	शेयर और डिबेंचर का पब्लिक इश्यू- वाणिज्यिक बैंकों की मर्चेंट बैंकिंग



			सहायक कंपनियों द्वारा हामीदारी
23.	बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 145/ 24.01.013-2000	07.03.2000	मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि के संबंध में दिशानिर्देश
24.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 120/ 24.01.002/ 99-2000	02.11.1999	गिल्ड फंड तथा लिक्विड इनकम योजना के निवेशकों के लिए चेक लिखने की सुविधा
25.	बैंपविवि. सं. एफएससी. 99/ 24.01.013/ 99-2000	09.10.1999	मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए चेक लिखने की सुविधा
26.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 70/ 24.01.001/ 1999-2000	17.07.1999	ईक्विपमेंट लीजिंग गतिविधि- लेखांकन / प्रावधानीकरण मानदंड
27.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 65/ 24.01.001/ 1999-2000	01.07.1999	वित्तीय सेवा कंपनियों की शेयर पूंजी में प्रतिभागिता
28.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 42/ 24.01.013/ 1999-2000	29.04.1999	मनी मार्केट म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए चेक लिखने की सुविधा
29.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 118/ 24.76.02/ 1998-1999	26.12.1998	पोर्टफोलिओ मनेजमेंट सेवा के लिए सूचना प्रणाली
30.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 129/ 24.76.02/ 1997-1998	22.10.1997	सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री
31.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 90/ 24.76.02/ 1997-1998	13.08.1997	ईक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेस, फॅक्टरिंग, आदि गतिविधियां
32.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 74/ 24.76.02/ 1995-1996	13.06.1996	बैंकों द्वारा म्यूचुअल फंड यूनिट की मार्केटिंग
33.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 129/ 24.76.02/ 1997-1998	08.06.1996	सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री
34.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 101/ 24.01.01/1995-96	20.09.1995	उपस्कर पट्टेदारी, अवक्रय, आदत आदि गतिविधियां
35.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 86/ 24.01.01/1995-96	17.08.1995	हामीदारी अंकन से संबंधित प्रतिबद्धताएं आदि - दायित्व
36.	बैंपविवि. सं. बीसी. 73/ 27.07.01/1994-95	07.06.1994	पोर्टफोलियो प्रबंध योजना (पीएमएस) कर तहत जमाराशियां स्वीकार किया जाना
37.	आईसीडी सं. 44/ 08.12.01/1994-95	27.04.1995	आदत सेवाएं -बैंकों की भूमिका-स्पष्टीकरण
38.	बैंपविवि. सं. बीसी. 69/	21.05.1994	बैंकों द्वारा म्यूचुअल फंड का कारोबार

	24.01.03/1994		करने लिए दिशानिर्देश
39.	बैंपविवि. सं. बीसी. 18/ 24.01.01/1993-94	19.02.1994	उपस्कर पट्टेदारी, अवक्रय, आढत आदि गतिविधियां
40.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 4/ 13.07.05/1994	25.01.1994	सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी बाँड में निवेश और हामीदारी
41.	बैंपविवि. सं. बीसी. 183/ 27.07.03/1993-94	18.10.1993	पोर्टफोलियो प्रबंध सेवाओं (पीएमएस) के लिए सूचनाप्रणाली
42.	बैंपविवि. सं. बीसी. 176/ 13.07.03/1994	11.10.1993	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा जारी बाँड में निवेश और हामीदारी
43.	बैंपविवि. सं. बीसी. 145/ 13.07.05/1993	30.07.1993	हामीदारी गतिविधि - हामीदारों पर न्यागमन
44.	बैंपविवि. सं. बीसी. 94/ 24.01.01/1992-93	19.03.1993	अनुषंगियों / म्यूच्युअल फंड की गतिविधियों की निगरानी
45.	बैंपविवि. सं. बीसी. 11/ 24.01.09/1992-93	30.07.1992	बैंकों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंध
46.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 45/ सी. 469-91/92	15.10.1991	वित्तीय सेवाएं कंपनियों की शेयर पूंजी में हिस्सेदारी / भारत में ओ.सी. एक्स्चेंज की सदस्यता लेना
47.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 130/ सी. 469-90/91	30.05.1991	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पट्टेदारी कारोबार का संचालन - स्पष्टीकरण
48.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 69/ सी. 469-90/91	18.01.1991	ग्राहकों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंध
49.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 14/ सी. 469-90/91	07.09.1990	बैंकों द्वारा अवक्रय कारोबार
50.	आईसीडी सं. पीएमडी. 1/ 50/90-91	02.07.1990	आढत सेवाओं के प्रावधान के लिए दिशानिर्देश
51.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 103/ सी.347(पीएसबी)-89	03.04.1989	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा जारी बाँड में निवेश और हामीदारी
52.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 27/ सी. 469-89	29.09.1989	शेयर, ऋणपत्रों आदि के पब्लिक इश्यू के लिए सेफ्टी नेट योजनाएं
53.	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 26/ सी. 469-89	29.09.1989	शेयर, ऋणपत्रों आदि के पब्लिक इश्यू से संबंधित प्रतिबद्धताएं आदि

54.	बैंपविवि. सं. बीपी(एफएससी). 1854/ सी. 469-89	27.05.1989	सहायक कंपनियों के निर्माण के लिए अनुमोदन
55.	बैंपविवि. सं. बीपी(एफएससी). बीसी 120/ सी. 469-89	02.05.1989	ग्राहकों के लिए पोर्टफोलियो प्रबंध
56.	बैंपविवि. सं. जीसी. बीसी 55/ सी. 408 सी(पी)-87	28.05.1987	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा जारी बॉण्ड में निवेश और हामीदारी
57.	बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 43/ सी 347 -87	15.04.1987	ग्राहकों के लिए पोर्टफोलियो मनेजमेंट
58.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 138/ सी.469(डब्ल्यू)-86	17.12.1986	बैंको द्वारा सहायक कंपनियों की स्थापना
59.	बैंपविवि. सं. जीसी. बीसी. 131/ सी 408 सी (पी)/ 86	25.11.1986	शेयर और डिबेंचर में निवेश
60.	आईसीडी सं सीएडी.92/ सी. 446(एलएफ)- 84	18.08.1984	इक्विपमेंट लीजिंग- बैंकों के लिए दिशानिर्देश